

प्रेषक,

सी.एस. नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 14 जुलाई, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में "अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय" योजनान्तर्गत वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि को व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-322/नि.अ.क./924-बजट मांग/2017-18, दिनांक 21.06.2017, शासनादेश संख्या-625/XVII-3/2017-01(03)/2017, दिनांक 25.04.2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में 'राजस्व' पक्ष की 'अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय' योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹ 54.42 लाख के सापेक्ष उपरोक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा पूर्व में स्वीकृत धनराशि ₹ 18.13 लाख के पश्चात् संलग्न विवरणानुसार ₹ 35.16 लाख (₹ पैंतिस लाख सौलह हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेशों द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते हुए मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
2. उक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के प्रस्तर-11 के प्राविधानानुसार अवचनबद्ध मदों की आवश्यकताओं को बजट प्राविधान की सीमा तक ही सीमित रखते हुए धनराशि का व्यय किया जाएगा।
3. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. कम्प्यूटर आदि क्रय के पूर्व एन.आई.सी./आई.टी. विभाग की नियमानुसार संस्तुति प्राप्त कर ली जायेगी।
7. फर्नीचर/उपकरण/कम्प्यूटर आदि के आवंटन के समय पदधारकों को नियमानुसार अनुमन्यता/मानकों एवं न्यूनतम आवश्यकता का परीक्षण कर क्रय किया जाएगा।
8. उपकरणों/निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
10. मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में 'अनुदान संख्या-15' के 'राजस्व' पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक संख्या "2250-अन्य सामाजिक सेवायें-800-अन्य व्यय-18-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय" के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित लेखाशीर्षक की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संख्या: SI707150286, दिनांक 14 जुलाई, 2017 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।
- संलग्न : यथोपरि। (कम्प्यूटर आई.डी. के अनुसार)

भवदीय,

(सी.एस. नपलच्याल)
सचिव।

संख्या: 1246 (1)/XVII-3/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी. एस. भाकुनी)
उप सचिव।